आपकी खबरों का संसार...

अतुल्य संसार

RNI No.-RJHIN/2015/63826

संस्करण: जयपुर

हिन्दी समाचार पत्र...

web: www.atulyasansar.com

Digital Edition

www.liveworldnews.in

वर्ष: 11 | अंक: 30 | जयपुर, गुरुवार 13 अगस्त, 2026 | मूल्य: 2 रुपए | पृष्ठ: 4

हरियाली अमावस्या... पेज 2

कैश कांड में... पेज 3

तेज बारिश से राजधानी की सड़के लबालब...

जयपुर। जयपुर में सुबह से तेज धूप के बाद दोपहर को मौसम में बदलाव हुआ। शहर में बुधवार को दोपहर बाद काले घने छाए बादल जमकर बदसे। इससे सडकें लबालब हो गईं। वहीं कई जगह जाम भी लग गया। छ्रस्ह मार्ग पर पानी भरने से जहां गाडियां रेंग-रेंग कर चलती रहीं। वहीं परकोटा क्षेत्र में कई दोपहिया वाहन बंद हो गए। मौसम विभाग ने शॉर्ट टर्म फोरकास्ट जारी करते हुए जयपुर शहर और उसके आसपास के एरिया में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश से जगह-जगह पानी भर गया। जिले में फागी, आमेर, चाकसू, चौमूं, जालसू, जमवारामगढ़ समेत कई इलाकों में 1 से 2 इंच तक पानी बरसा।

फागी में सबसे ज्यादा बरसात

पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात फागी में 42 एमएम दर्ज हुई। वहीं सांगानेर एरिया में 22एमएम, तूंगा में 22, शाहपुरा में 15, सांभर में 11, रामपुरा डाबरी में 14, कोटखावदा में 18, जमवारामगढ़ में 35, जालसू में 21, जयपुर कलेक्ट्रेट पर 21, जेएलएन मार्ग पर 15, चौमूं में 32, चाकसू में 23 और आमेर के आसपास 39एमएम बरसात दर्ज हुई। इनके अलावा आंधी, बस्सी, दूदू, जोबनेर, कालवाड़, किशनगढ़-रेनवाल, मौजमाबाद, माधोराजपुरा, नरैना, फुलेरा के एरिया में भी हल्की बारिश हुई।

25 फीसदी कम हुई बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक- जयपुर में अब तक सीजन में कुल 255.8 एमएम बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 25 फीसदी कम है। राज्य में 1 जून से 11 अगस्त तक औसत बरसात 341 एमएम होती है।

सुबह रही धूप, दोपहर बाद मौसम में बदलाव

जयपुर में सुबह कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन दिन में कुछ समय के लिए मौसम शुष्क रहा। कुछ जगह हल्की धूप निकली और उमस बढ़ गई। दोपहर करीब 3 बजे बाद फिर से मौसम में बदलाव हुआ और बादल छाने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया, जो लगातार जारी रहा। जयपुर शहर में अजमेरी गेट, चारदीवारी, रेलवे स्टेशन, बाइस गोदाम सर्किल, रामबाग, टोंक फाटक समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात हुई। टोंक रोड पर जगह-जगह पानी भरने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई।

JLN मार्ग पर ट्रैफिक-जाम:परकोटा में स्कूटी बंद; फागी-चौमूं में हुई 2 इंच पानी बरसा

जेएलएन मार्ग पर पानी भरने से रेंग-रेंग कर चलती रहीं गाडियां

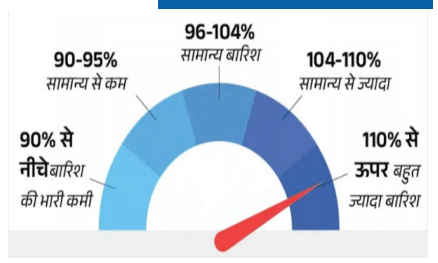

बारिश के बाद शहर के पॉश इलाकों सहित निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। इससे आम लोगों के साथ बाइक और कार सवार परेशान होते रहे। कई जगह गाडियां रेंग-रेंग कर चलती रहीं।

शहर में जगह-जगह पानी भरा

शहर में बारिश के बाद पानी के नहीं निकलने से जगह-जगह भराव हो गया। इससे गाडी सवार परेशान होते रहे। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद बारिश का दौर तेज हो गया। चारदीवारी इलाके में बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरने से नदी जैसे हालात हो गए। जयपुर में बारिश के बाद 22 गोदाम सर्किल पर जाम की स्थिति बन गई। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

हाईकोर्ट ने कहा-द्रव्यवती में केवल द्रव्य (एसिड) ही रह गया

पानी तो रहा नहीं; जेडीए से मांगी अतिक्रमणों की सूची, अधिकारियों को किया तलब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर शहर के बीच में से निकल रही द्रव्यवती नदी में गंदगी और अतिक्रमण को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- द्रव्यवती में अब केवल द्रव्य (एसिड) ही रह गया है, पानी तो बचा नहीं। कोर्ट ने जेडीए को द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमणों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं अगली सुनवाई तक सरकार को यह भी बताना है कि द्रव्यवती नदी की जमीन से जुड़े मुकदमे किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

सरकार को दिया जवाब का अंतिम मौका

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र शोभित तिवाड़ी ने कोर्ट को बताया- फरवरी में अपनी रिपोर्ट में मैंने कई कमियों को उजागर किया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 6 महीने बाद भी सरकार समय ही मांग रही है। हम सरकार को अंतिम मौका दे रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा- जेडीए अतिक्रमण का नियमन कर रहा

मामले में याचिकाकर्ता पीएन मैंदोला ने कहा- नदी क्षेत्र की जमीन के कई खसरों पर अतिक्रमण हो गया है और जेडीए इनमें से कई का नियमन भी कर रहा है। इस पर जेडीए की ओर से कहा गया कि हम अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कई जगह पर कोर्ट की रोक की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस पर हाईकोर्ट ने इन मुकदमों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए।

पृथ्वीराज नगर में बुलडोजर का खौफ

JDA ने थमाए 1000 नोटिस, 18 किमी क्षेत्र में 25 हजार निर्माण और 1 लाख आबादी पर संकट

जयपुर। राजधानी जयपुर के बड़े आवासीय क्षेत्र पृथ्वीराज नगर में हाई-टेंशन बिजली लाइनों के राइट ऑफ वे को लेकर एक बार फिर जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अजमेर रोड से गोपालपुरा बाईपास के बीच करीब 3 किलोमीटर के दायरे में बने 800 मकानों और 200 दुकानों को जेडीए द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद स्थानीय निवासियों में तोड़फोड़ का भारी डर व्याप्त हो गया है। अगर यही नीति कालवाड़ से सांगानेर तक के पूरे 18 किलोमीटर क्षेत्र में लागू होती है, तो करीब 25,000 रिहायशी व व्यावसायिक निर्माण और लगभग 1 लाख की आबादी इस बेदखली की सीधी ज़द में आ जाएगी।

सालों से आशियाने, अब उजड़ने का खतरा:

विवाद की मुख्य वजह वर्षों पुरानी हाई-टेंशन बिजली लाइनें और उनके नीचे या आसपास बसी घनी आबादी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई क्षेत्रों में मकान लाइनों के बनने से पहले से मौजूद हैं, तो कहीं बाद में बने। दशकों से रह रहे लोगों को अब अचानक नोटिस देकर बेघर करने की तैयारी की जा रही है। 13 अगस्त को होने वाली आगामी सुनवाई से ठीक पहले जेडीए की इस कार्रवाई से आक्रोशित निवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

राजस्थान में 4 हजार किलो ड्रग्स नष्ट करवाए

इस साल जुलाई तक 5 हजार मामले दर्ज; NCB का नशे के खिलाफ अभियान

जयपुर। राजस्थान में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में NCB ने अब तक करीब 4 हजार किलो ड्रग्स जब्त कर नष्ट की है। NCBके अनुसार प्रदेश में 2025 में मादक पदार्थों से जुड़े 6 हजार 387 मामले दर्ज हुए थे। वहीं जुलाई 2026 तक करीब 5 हजार मामले सामने आ चुके हैं। डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी से हो रही ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' को राजस्थान के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए बुधवार को PIB जयपुर की ओर से मीडिया वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें PIB , केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नशे के बढ़ते खतरे और रोकथाम के उपायों की जानकारी दी। NCB के जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा ने बताया- गृह मंत्रालय ने जून 2026 में 'विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029)' जारी किया है।

गहलोत बोले...जब अपने ही सरकार के खिलाफ मंत्री धरने पर बैठे तो इससे बड़ा प्रशासनिक निक्कमापन क्या होगा?

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भजनलाल सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा अपनी ही सरकार में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अलवर नगर निगम के सामने धरने पर बैठ गए। मामला वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र वितरण से जुड़ा हुआ था। मंत्री संजय शर्मा का आरोप था कि जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन लगातार इस मामले में टालमटोल कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के सामने आते ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि जब कैबिनेट स्तर का मंत्री अपने ही जिले में जायज काम के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है, तो इससे बड़ा प्रशासनिक निकम्मापन और कुछ नहीं हो सकता।

अफसरशाही के आगे बेबस मंत्री, सिर्फ रबर स्टैंप

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की अफसरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा राज में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं रह गई है। गहलोत ने लिखा कि मंत्री संजय शर्मा ने जिला कलेक्टर से बात की, लेकिन इसके बावजूद अफसरशाही ने अपने ही मंत्री की एक न सुनी।

इससे साफ साबित होता है कि भाजपा राज में सरकार जन प्रतिनिधियों के बजाय बेलगाम अफसरों के इशारे पर चल रही है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं।

डांगावास फैसले के विरोध में जयपुर में उमड़ा जनसैलाब

करीब 5 हजार लोगों ने शहीद स्मारक पर दिया धरना, 36 कौम ने एक स्वर में कहा—इंसानियत बड़ी बात है, न्याय होना ही चाहिए

जयपुर। डांगावास हत्याकांड में विशेष न्यायालय, मेड़ता सिटी द्वारा सभी 40 अभियुक्तों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ बुधवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, राजस्थान, जयपुर के नेतृत्व में विशाल धरना आयोजित किया गया। धरने में राजस्थानभर से करीब पांच हजार लोग शामिल हुए। फैसले को लेकर समाज में दिखाई दे रहे भयंकर आक्रोश के बीच प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग न्याय की आवाज को मजबूती देने जयपुर पहुंचे। धरने में डांगावास हत्याकांड के पीड़ित परिवारों की ओर से गोविंद मेघवाल, मोहन मेघवाल, धन्नाराम मेड़ता और बगड़ाराम मेड़ता भी शामिल हुए। वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवारों की मौजूदगी ने धरने को भावनात्मक और गंभीर स्वरूप दिया। धरने में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 36 कौम के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे। आंदोलन को समर्थन देने आए लोगों ने कहा कि डांगावास का मामला किसी एक समाज का नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय का सवाल है। उन्होंने एक स्वर में कहा-इंसानियत बड़ी बात है, न्याय होना ही चाहिए। धरने को संबोधित करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस सत्यवीर सिंह ने कहा कि डांगावास की भयावह घटना में पांच लोगों की हत्या हुई और अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ित परिवार करीब ग्यारह वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में सभी 40 अभियुक्तों के बरी होने के फैसले से पीड़ित परिवारों और समाज में गहरा आक्रोश एवं निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। सत्यवीर सिंह ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन कानून द्वारा उपलब्ध वैधानिक उपायों का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार है। सरकार को चाहिए कि फैसले के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रभावी अपील दायर कराए और मामले की मजबूत एवं निष्पक्ष पैरवी सुनिश्चित करे। ज्ञापन में भी हाईकोर्ट में तत्काल अपील, अनुभवी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति तथा प्रभावी पैरवी की मांग की गई है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष आर.पी. बैरवा ने भी धरने को संबोधित करते हुए कहा कि डांगावास के पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक लोकतांत्रिक और वैधानिक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर से जिस तरह 36 कौम के लोग इस आंदोलन के समर्थन में आए हैं, वह सामाजिक एकजुटता और इंसानियत की ताकत का प्रमाण है। धरने को दौसा विधायक डी.सी. बैरवा, पिलानी विधायक पितराम काला, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, पूर्व विधायक पूरन सैनी खेतड़ी, जय नारायण शेर, श्रीराम चोरड़िया, बी.एल. बैरवा, टेकचंद राहुल, जे.पी. विमल, रवि मेघवाल, राकेश जॉय, गीगराज जोड़ली, महेंद्र खंडेलवाल, भंवर लाल सांभरिया एवं विनोद वर्मा रलावता सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। 36 कौम की भागीदारी ने यह संदेश दिया कि न्याय की लड़ाई किसी एक जाति या समुदाय की लड़ाई नहीं होती। जब किसी परिवार के साथ अन्याय होता है तो इंसानियत का तकाजा है कि समाज उसके साथ खड़ा हो। धरने के बाद प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विशेष न्यायालय के फैसले के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट में तत्काल वैधानिक अपील दायर कराने, पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा मामले की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में पीड़ित परिवारों और महत्वपूर्ण गवाहों की सुरक्षा का तत्काल पुलिस स्तर पर ऑडिट कराने तथा आवश्यकता के अनुसार प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई, ताकि किसी प्रकार का भय, दबाव या धमकी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। वक्ताओं ने कहा कि डांगावास प्रकरण केवल एक आपराधिक मुकदमा नहीं है, बल्कि यह न्याय, मानवीय संवेदना, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। करीब ग्यारह वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के दर्द को समझते हुए सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। धरने में उमड़े हजारों लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया कि डांगावास के पीड़ित परिवार अकेले नहीं हैं। राजस्थान का समाज उनके साथ खड़ा है और न्याय की इस वैधानिक लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा।

पचलंगी में 33/11 केवी जीएसएस का शिलान्यास आज

सुमेर सिंह राव/उदयपुरवाटी। उपखंड क्षेत्र के पचलंगी कस्बे के लोगों के लिए लंबे इंतजार के बाद अब लोगों को जल्द मिलेगी बिजली फाल्ट की समस्या से राहत। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने 1 जुलाई को पचलंगी में 33/11 केवी विद्युत जीएसएस को स्वीकृति दे दी थी ।जिसका शिलान्यास आज गुरुवार को होगा। मंगलवार को झड़ाया नगर के भावरीया की ढाणी में एक शोक सभा में पहुंचे पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने ग्रामीणों को बताया कि गुरुवार को सुबह 10 बजे कस्बे की इन्द्राआवास कॉलोनी के पास में पूर्व में जीएसएस के लिए लगाई गई चारदीवारी में जीएसएस के निर्माण कार्य का शिलान्यास होगा ।इस दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के अस्थाई निलंबन को आरसीए के प्रशासक भास्कर सावंत ने किया रद्द

दीपचंद शमा भरतपुर। राजस्थान क्रिकेट संघ की पूर्व एडहॉक कमेटी के तत्कालीन कन्वीनर मोहित यादव द्वारा जिला क्रिकेट संघ भरतपुर का 9 जून 2026 को अस्थायी रूप से निलंबन कर दिया गया था । निलंबन के पीछे संघ के सचिव शत्रुघन तिवारी पर गंभीर प्रकृति की शिकायत प्राप्त होने बताया था और बाद में चार सदस्य वाली जांच समिति पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व मे नियुक्त गई थी परंतु राजीव प्रताप सिंह के द्वारा हाईकोर्ट मे दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 1 जुलाई 2026 के अपने आदेश में तत्कालीन मोहित यादव वाली एडहॉक कमेटी को निरस्त करते हुए राजस्थान सरकार के होम सेक्रेटरी भास्कर सावंत को राजस्थान क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त किया गया था । उक्त सभी शिकायतों पर भास्कर सावंत द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए भरतपुर के संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर उक्त प्रकरण में एक जांच कमेटी नियुक्त करने को कहा ।संभागीय आयुक्त द्वारा तीन सदस्य जांच कमेटी नियुक्त की गई जिसमें श्रेष्ठ श्री आई ए एस को अध्यक्ष एवं दो आर ए एस अधिकारियों को सदस्य शामिल किया । कमेटी ने सभी शिकायतकर्ता और शत्रुघ्न तिवारी को सुनवाई का अवसर देकर जांच को पूर्ण किया और अपनी जांच में कहा कि सभी शिकायतकर्ता जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी के खिलाफ कोई भी ठोस साक्ष्य और सबूत जांच कमेटी के सामने पेश नहीं कर पाए । उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आरसीए के प्रशासक भास्कर सावंत ने जिला क्रिकेट संघ भरतपुर की अस्थाई निलंबन को रद्द करते हुए चुनाव में भाग लेना वोट करना तथा संघ के सभी अधिकारों को बहाल किया।

पचलंगी की पूर्व सरपंच कमला भावरिया को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता

पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला व नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित

खंडेला विधायक सुभाष मील भी पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने

सुमेर सिंह राव/उदयपुरवाटी। उपखंड क्षेत्र के पचलंगी पंचायत की पूर्व सरपंच स्वर्गीय कमला भावरिया का आकस्मिक निधन होने पर जहां उनके परिवार में शोक का माहौल है वहीं कई लोगों ने पूर्व सरपंच कमला भावरिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला ने स्वर्गीय कमला भावरिया की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा की स्वर्गीय कमला भावरिया एक सच्ची समाज सेविका तो थी ही विकास के कामों में हमेशा अग्रणी रहती थी द्य बुधवार को उनके आवास पर स्वर्गीय कमला भंवरिया की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला ,नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी, खंडेला विधायक सुभाष मील, रमेश खंडेलवाल पूर्व विधायक नीमकाथाना, राजेंद्र यादव प्रधान प्रतिनिधि नीमकाथाना ,वीर तेजाजी सेवा समिति नीमकाथाना ,हरि सिंह, प्रिंसिपल वेद प्रकाश ,भागीरथमल चौधरी , पूर्ण प्रकाश यादव , पूरणमल भाकर , नवरंगपुरा के समाजसेवी ताराचंद भावरिया, लक्ष्मण सिंह कुड़ी, डॉ रामकुमार सिराधना, कैप्टन रामनिवास ताखर सहित हजारों की तादाद में कई गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण -संक्षिप्त जानकारी

(मंगल चंद सैनी पूर्व तहसीलदार)

आगामी दिनों में पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ संपन्न होने जा रहे हैं इनमें विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार है- 1.पूरे प्रदेश में एससी एसटी की पृथक पृथक जनसंख्या 2011 के अनुसार जितना प्रतिशत है उतनी ही सीटें जिला प्रमुख व नगर निकाय प्रमुख के लिए आरक्षित होंगी 2.पूरे जिले की कुल जनसंख्या में एससी एसटी की पृथक पृथक प्रतिशत के बराबर जिला परिषद व प्रधान की सीटें आरक्षित होंगी ।3.पूरी पंचायत समिति की जनसंख्या में एससी एसटी की पृथक पृथक प्रतिशत जितनी सरपंच व पंचायत समिति सदस्य की सीटें आरक्षित होंगी । 4.पूरी पंचायत/नगर निकाय में एससी एसटी की पृथक पृथक जनसंख्या के जितनी पंच/पार्षद की सीटें आरक्षित होंगी ।

5.यदि आरक्षित वर्ग की जनसंख्या पाँच प्रतिशत से कम है तो आरक्षण लागू नहीं होगा । 6.ओबीसी वर्ग को अधिकतम 21 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा उससे कम होने पर उतना ही आरक्षण मिलेगा । 7.इस बार पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का आरक्षण नई सूची के अनुसार मिलेगा ।नया अधिनियम लागू होने के समय एससी एसटी के आरक्षण हेतु बनाई गई सूचि के अनुसार आरक्षण होगा चाहे पंचायत समिति या पंचायत का पुनर्गठन हुआ हो हाँ यदि सूचि की समस्त पंचायतें आरक्षण का कोटा पूरा कर चुकी हों तो नई सूची तैयार की जाएगी ।नवघोषित पंचायतों को पुरानी सूचि में जोड़ा जाएगा। आरक्षण का यह प्रावधान पंचायती राज अधिनियम की धारा 14,15 में किया हुआ है।

(लेखक के ये निजी विचार हैं) ?

हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई लोहार्गल के सूर्य कुंड में डुबकी

गोमुख की जलधारा से की पूजा-अर्चना, पवित्र कुंड में स्नान कर कमाया दान-पुण्य

सुमेर सिंह राव/उदयपुरवाटी। निकटवर्ती शेखावाटी के प्रसिद्ध तीर्थराज लोहार्गल धाम में बुधवार को हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन मास की अमावस्या पर अलसुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लोहार्गल धाम पहुंचकर पवित्र कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। लोहार्गल कुंड से मिली जानकारी के अनुसार, पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गोमुख की बहती जलधारा से विशेष पूजा-अर्चना की। सावन के महीने का विशेष योग होने के कारण भक्तों ने देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का जलाभिषेक कर खुशहाली की मन्नतें मांगी। अमावस्या के चलते धाम

के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं, जहाँ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर शीश नवाया। कांवड़ियों की गूंज और दान-पुण्य का दौरपवित्र श्रावण मास के चलते लोहार्गल धाम में इन दिनों कांवड़ियों और दूर-दराज से आने वाले जातरुओं का तांता लगा हुआ है। बम-बम भोले और जय बाबा की के जयकारों से पूरा क्षेत्र धर्ममय हो उठा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व होने के कारण पुरुषों और महिलाओं ने मंदिरों में पूजा-अर्चना के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार खुलकर दान-पुण्य किया। महिलाओं ने भी इस विशेष पर्व पर उपवास रखकर सुख-समृद्धि की कामना की।

'एक पेड़ एक शिक्षक के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

हिण्डोली। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हिण्डोली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में एक पेड़-एक शिक्षक के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिकों को अधिकाधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में सीबीईओ सुमित्रा मीणा, एसीबीईओ प्रथम बुद्धाराम बिश्नोई , एसीबीईओ द्वितीय फोरूलाल रैगर एवं आरपी प्रथम बृजराज सिंह हाडा तथा ब्लॉक कार्यालय कर्मचारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, वैभव जैन, राजेश जैन, सुरेश यादव, मनराज धाकड़, ऋषभ शर्मा, जितेंद्र प्रजापत, कमलेश बिश्नोई, राजेश मीणा, मोहनलाल सैनी, शंकरलाल सैनी तथा राजेश झा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षक संघ के पदाधिकारी महेंद्र गौड़, पूर्णसिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, भगवान सोनी, कुलदीप सोलंकी, कमलेश कुमार मीणा, भगवान दाधीच, हरिराम गुर्जर एवं नरेश कुमार मीणा सहित अन्य

पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि एक पेड़-एक शिक्षक के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित न रहकर पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का भी संकल्प है। प्रत्येक शिक्षक यदि एक पौधे को अपने नाम से लगाकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाए, तो यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। डड एक शिक्षक -एक पेड़ - एक संकल्प, हरित एवं स्वच्छ भविष्य की ओर एक सार्थक पहल।

मा. आ. जी. राजकीय महाविद्यालय, डीग में 10-दिवसीय 'एआई प्राईम - डिजिटल प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम' के ऑनलाइन कोर्स का सफल शुभारंभ

दीपचंद शर्मा डीग। मा. आ. जी. राजकीय महाविद्यालय, डीग के प्लेसमेंट सेल द्वारा एनआईआईटी फाउंडेशन एवं इन्फोसिस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10-दिवसीय नि:शुल्क कौशल विकास पाठ्यक्रम एआई प्राईम - डिजिटल प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के ऑनलाइन नियमित कोर्स का प्रथम दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कक्षा के प्रथम दिन आयोजित विशेष ओरिएंटेशन सत्र के दौरान विद्यार्थियों को आगामी 09 दिनों में आयोजित होने वाली कक्षाओं की रूपरेखा, प्रशिक्षण मॉड्यूल और कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. दिलीप सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एआई आधारित यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों को आधुनिक कार्यबल की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगा। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से प्रत्येक सत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहकर इस तकनीकी ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाने का आह्वान किया। विषय विशेषज्ञ ऋषभ आनंद ने कोर्स के प्रमुख मॉड्यूल्स जैसे- एआई ऑटोमेशन टूल्स के व्यावहारिक उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इन मॉड्यूल्स को पूरा करने से विद्यार्थियों की डिजिटल उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, कोर्स पूरा करने के लिए

आवश्यक उपस्थिति, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और अंतिम मूल्यांकन के मानदंडों के बारे में भी विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। प्लेसमेंट सेल समन्वयक डॉ. चन्द्र प्रभा महावर ने बताया कि प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा तथा प्लेसमेंट सेल के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर प्लेसमेंट सेल सदस्य लक्ष्मी नारायण मीना एवं लक्ष्मी यादव जी सहित महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ. ईशा शर्मा, श्वेता, राजाराम, डॉ. महेश चंद महावर, संदीप रैगर, डॉ. अखिल भारद्वाज, विनय कुमार बैरवा, रोनित यादव, स्वीटी आशवानी एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी उपस्थित रहे, तथा बड़ी संख्या में पंजीकृत विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में प्लेसमेंट सेल सदस्य ओमवीर सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

महेंद्र गुर्जर को भारतीय कुश्ती टीम की कमान

नीमकाथाना के पास भगेगा निवासी है महेंद्र गुर्जर

सुमेर सिंह राव /नीमकाथाना । नीमकाथाना के ग्राम भगेगा निवासी महेंद्र गुर्जर को बहरीन में 16 से 23 अगस्त तक ब्राटिशलावा स्लोवाकिया में हो रही अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की कुश्ती टीम का कोच नियुक्त किया गया है द्य उनकी यह नियुक्ति भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा की गई है महेंद्र गुर्जर पूर्व में जुलाई 2025 में किर्गिस्तान में हुई अंडर 20 एशिया चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता वहयूथ एशियन गेम्स मनामा बहरीन में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं । भगेगा निवासी महेंद्र वर्तमान में आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर भोपाल तैनात हैं तथा खुद भी अंतरराष्ट्रीय पहलवान रह चुके हैं एवं रेलवे में कुश्ती कोच है द्य महेंद्र सन 2019 में चीन में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस प्रतियोगिता में सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं उनकी नियुक्ति पर उनको राजस्थान कुश्ती संघ के द्वारा बधाई दी गई ।

मानगढ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए आदिवासी समाज ने दिया ज्ञापन

झुंझुनू जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

सुमेर सिंह राव/ उदयपुरवाटी । आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रतन मीना जोधपुरा के नेतृत्व मे आदवासी समाज ने जिला कलेक्टर को मानगढ धाम को राष्ट्रीय स्मारक धोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा । ज्ञात हो की 17 नवम्बर 1913 को गोविन्द गुरू के नेतृत्व मे एक लाख पचास हजार से अधिक आदिवासी मानगढ धाम मे औपनिवेशिक अत्याचार अनुचित करों ,जबरन बंधुआ मजदूरी के विरोध मे एकत्रित हुए थे। निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां बरसाई गई जिसमे 1500 आदिवासी शहीद हुए थे । यह भंयकर नरसंहार जलियांवाला हत्याकांड से पहले हुआ था । विवाद की स्थिति केन्द्रीय मंत्री के विवादित बयान के कारण पैदा हुई । इस अवसर बनवारी लाल मीना पूर्व जिलाध्यक्ष, रामचन्द्र मीना अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिला प्रवक्ता एडवोकेट धर्मवीर मीना, उपाध्यक्ष रामकुमार सिंह मीना भीमसर ,रोहिताश मीना भौडकी,दयानंद मीना,ओमप्रकाश मीना,राजेश मीना,जयपाल सिंह मीना,नवीन मीना,रामचंद्र मीना,कृष्ण कांत मीना सहित काफी संख्या मे आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

जेडीए की कार्रवाई पर ट्रिब्यूनल का आवासीय एंगल

90बी से बदली जमीन तो होटल-रिसॉर्ट के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी उठे सवाल

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट देशभर में अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्ती बरत रहा है। इसी बीच जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के आदेश ने जमीन के भू-उपयोग और उस पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जेडीए ने जिस संपत्ति को कथित अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि के मामले में नोटिस दिया। वहीं ट्रिब्यूनल के सामने जमीन के आवासीय होने का तर्क सामने आया।

कृषि भूमि पर चल रही व्यावसायिक गतिविधि

जेडीए के 13 जुलाई 2026 के नोटिस में संबंधित जमीन पर बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृति के व्यावसायिक गतिविधि संचालित किए जाने का आरोप लगाया गया था। वहीं 10 अगस्त के ट्रिब्यूनल आदेश में अपीलार्थी की ओर से दलील दी गई कि जमीन का 16 सितंबर 2005 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत भू-परिवर्तन हो चुका था और वह कृषि भूमि नहीं रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर जमीन आवासीय है तो क्या उस पर होटल

या रिसॉर्ट चलाना अपने आप वैध हो जाता है।

90बी के दायरे पर भी सवाल

इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि 90बी के तहत जमीन के कितने हिस्से का भू-परिवर्तन हुआ था। अगर केवल किसी हिस्से का भू-परिवर्तन हुआ था तो क्या उसके आधार पर पूरी संपत्ति को आवासीय माना जा सकता है। साथ ही क्या भू-परिवर्तन होने से बाकी हिस्से पर हुए निर्माण और उसके इस्तेमाल को वैधता मिल जाती है।

आवासीय जमीन का मतलब होटल की अनुमति नहीं

विशेषज्ञों के अनुसार- किसी जमीन का आवासीय भू-उपयोग होना अलग बात है। जबकि उस पर बने भवन का स्वीकृत होना अलग है। ऐसे में अगर किसी होटल या रिसॉर्ट का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के हुआ है। या स्वीकृत भवन योजना के विपरीत है तो सिर्फ आवासीय भू-उपयोग का हवाला देकर उसे वैध नहीं माना जा सकता। इसलिए यह भी अहम है कि संबंधित निर्माण का नक्शा पास है या नहीं और मौके पर मौजूद निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं। हालांकि, **JDAT** का आदेश रिसॉर्ट को अंतिम रूप से वैध घोषित करने वाला आदेश नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि मौके के निरीक्षण में व्यावसायिक गतिविधि पाई जाती है, तो **JDA** नियमानुसार नोटिस और आगे की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अब निगाह **JDA** की अगली कार्रवाई पर है। क्या वह 90बी के वास्तविक दायरे, जमीन के रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शे और मौके पर चल रही गतिविधि की अलग-अलग जांच करेगा। क्योंकि होटल का व्यावसायिक इस्तेमाल वैध नहीं है तो क्या उसे सिर्फ हवेली या आवासीय भवन बताकर कार्रवाई से बचाया जा सकता है।

कॉलेज प्राचार्य बर्खास्त, 10 सेवानिवृत अफसरों की पेंशन रोकी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अनियमितताओं और गंभीर कदाचार के मामलों में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति एवं धारा 17-ए के तहत कार्यवाही के अनुमोदन के साथ विभागीय जांच के गंभीर प्रकरणों का निस्तारण करते हुए करीब 40 मामलों में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के एक प्रकरण में कॉलेज के प्राचार्य को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, इस कृत्य में सहयोग करने वाले एक प्रवक्ता और पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सेवा से हटाने की मंजूरी दी गई है। भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने से जुड़े 6 गंभीर मामलों में सीएम भजनलाल शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, वित्तीय सलाहकार, सहायक अभियंता तथा विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया है।

कैश कांड में हाईकोर्ट जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप साबित

जांच समिति बोली- सबूतों से छेड़छाड़ हुई, नोटों की बोरी कहां से आई, नहीं बता पाए

नई दिल्ली। संसद की जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे तीनों आरोपों को सही पाया है। यह मामला 2025 में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोररूम से नकदी मिलने से जुड़ा है। पैनल की रिपोर्ट बुधवार, 12 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोररूम में 500 रुपए के नोटों की काफी मात्रा मिली थी।

लेकिन जस्टिस वर्मा नकदी के स्रोत, मालिकाना हक या वहां मौजूद होने की संतोषजनक वजह नहीं बता सके। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

जांच समिति ने पाया कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में 500 के नोटों के बंडल और अधजले नोट मिले थे। फायर सर्विस और पुलिस के कर्मचारियों ने जांच के दौरान बताया कि नोट सिर्फ एक जगह नहीं थे, बल्कि स्टोर रूम के बड़े हिस्से में फैले हुए थे। दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारी अंकित सहगल ने बताया कि उसने 500 के नोटों के बंडल देखे थे, जो स्टोर रूम में 7-8 फीट तक फैले हुए थे। पुलिस अधिकारी रूपचंद से जब पूछा गया कि क्या नकदी की मात्रा 5 लाख से ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा बहुत छोटा है। हालांकि, नोटों को जब्त नहीं किया गया, उनकी गिनती नहीं हुई और न ही नोटों के नमूने सुरक्षित किए गए। इसी वजह से समिति यह निर्धारित नहीं कर सकी कि वहां वास्तव में कितनी नकदी थी। आग बुझने के बाद स्टोर रूम को तुरंत सील नहीं किया गया। सुरक्षा अधिकारी ने जस्टिस वर्मा के स्टाफ को वहां रात करीब 3 बजे सफाई करते देखा। सुबह तक जला हुआ सामान बाहर निकाल दिया गया और कमरा साफ कर दिया गया।

वहां मिले नोट भी सुरक्षित नहीं किए गए और बाद में मिले भी नहीं। कमेटी ने माना कि इस तरह महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित नहीं रखे गए और उनसे छेड़छाड़ हुई।

नतीजा: आरोप साबित। **आरोप-3:** जस्टिस वर्मा के जवाब टालमटोल वाले और भ्रामक थे शुरुआत में जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें कैश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में बचाव में नकदी नकली होने, साजिश के तहत रखे जाने के बात कही। लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई स्वतंत्र शिकायत या ठोस सबूत सामने नहीं आया। जस्टिस वर्मा ने खुद भी गवाही नहीं दी और अपने परिवार या स्टाफ को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया।

इसी साल 9 अप्रैल को जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दिया

9 अप्रैल 2026 को जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने लिखा था कि, मैं आपके सम्मानित कार्यालय को उन कारणों से परेशान नहीं करना चाहता, जिनकी वजह से मुझे यह पत्र लिखना पड़ रहा है। लेकिन गहरे दुख के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।

खुदरा महंगाई लगातार सातवें महीने बढ़ी, खाने-पीने की चीजें महंगी

जुलाई में 4.45% रही, दूसरे महीने RBI के 4% के अनुमान से ज्यादा

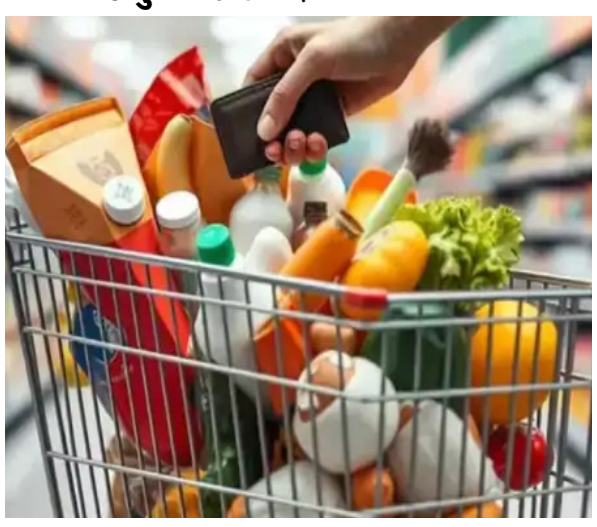

नई दिल्ली। आलू-प्याज जैसे खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से रिटेल महंगाई लगातार सातवें महीने बढ़ी है। जुलाई में यह 4.45% रही। एक महीने पहले जून में यह 4.38% पर थी। आज 12 अगस्त को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। खाने-पीने के सामानों की महंगाई यानी फूड इंफ्लेशन जुलाई में बढ़कर 5.52% पर पहुंच गई है। जून में यह आंकड़ा 5.32% पर था। मान लीजिए आपके घर में हर महीने 10 किलो प्याज लगता है। सामान्य दिनों में इसका रेट 30 प्रति किलो रहता था। यानी महीने का बजट 300। रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई दर का लक्ष्य 4% तय किया है। यह लगातार दूसरा महीना होगा जब रिटेल महंगाई आरबीआई के तय कम्फर्ट जोन 4% से ऊपर दर्ज की गई है।

महंगाई कैसे बढ़ती-घटती है?

महंगाई का बढ़ना-घटना प्रोडक्ट की डिमांड-सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। इससे चीजों की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं होने पर इनकी कीमत बढ़ेगी। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा तो महंगाई कम होगी।

तुलना पिछले साल से होती है (साल-दर-साल)

जब हम कहते हैं कि जुलाई 2026 में महंगाई 4.45% है, तो इसका मतलब है कि हम इसकी तुलना जुलाई 2025 से कर रहे हैं। यह पूरे एक साल का बदलाव है। 4.45% एक औसत नंबर है जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। किसी चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े होंगे। किसी चीज के दाम घटे भी होंगे। जब इन सबको एक साथ मिलाया गया, तो औसतन खर्च 4.45% बढ़ गया। इसका गणित बहुत सीधा है। अगर जुलाई 2025 में आपने कोई सामान जैसे राशन 100 में खरीदा था, तो वही सामान जुलाई 2026 में 104.45 का हो गया है।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा

नई दिल्ली। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आज 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 18 अगस्त को होने वाली टाटा संस की एजीएम से ठीक पहले आया है। हालांकि, वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर टाटा ट्रस्ट्स के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। नए कारोबारों में भारी निवेश, उनके प्रदर्शन और टाटा संस के भविष्य को लेकर मतभेद इस फैसले की बड़ी वजह बने। एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर के बाद टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में गिरावट है। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर के शेयर 3त्न तक नीचे हैं। चंद्रशेखरन ने कहा कि, टाटा संस के चेयरमैन के रूप में मेरा मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म हो रहा है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके मेरे अगले 5 साल के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश की थी।

शाह बोले- स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करें: मैं सदन में रहूंगा

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की। इससे पहले सुबह सदन के बाहर शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है। पहले ये बताएं कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। उन्होंने आदेश नहीं दिया तो वे इस्तीफा दें।' इस बीच सरकार ने FCRA संशोधन बिल, 2026 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। शाह ने पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान दिया, कहा- रोज सदन में आ रहा हूं।

राहुल बोले- शाह सदन में क्यों नहीं आए

राहुल ने कहा- स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी? स्टूडेंट्स को कीलों वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल ने आगे कहा- शाह घर के सामने हजार पुलिस वाले खड़े होते हैं। 30 गाड़ियां उनके आगे पीछे होती हैं कि कहीं कोई बच्चा न आ जाए।

FCRA संशोधन बिल JPC को भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास

लोकसभा ने हंगामे के बीच **FCRA** संशोधन बिल, 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया। इसपर संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि कुछ बिलों को **JPC** के पास भेजा जाता है और सरकार भी यही कर रही है। बिल में कुछ आपत्तिजनक है तो विपक्ष **JPC** के सामने अपनी बात रख सकता है।खुश होने के चक्कर में इसका विरोध करना अफसोस की बात है। वहीं, अखिलेश यादव ने **FCRA** बिल का विरोध करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है। रिजिजू के इस दावे पर कि बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, अखिलेश ने सवाल किया- आप बताइए कि कौन सा बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है?

खड़गे बोले- शाह के रोज गैरहाजिर होने का धंधा, नड्डा बोले- आप चर्चा से भाग रहे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अमित शाह की सदन में गैरहाजिरी पर निशाना साधते हुए कहा- जिनके नाम से बिल है, किसी कारण से वे अबसेंट हैं तो वो चलेगा। लेकिन उनका रोज का धंधा हो गया है। उन्हें बुलाइए। जेपी नड्डा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप चर्चा से भागिए मत।

पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं। गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है। वह सदन में नहीं आ सकते।

शाह का लोकसभा स्पीकर को लेटर,

हमें लेक्चर नहीं सुनना...राहुल

कहा- चर्चा के लिए समय तय करें

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखा। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान सरकार की ओर से **NEET** परीक्षा को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने पर सहमति जताई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया। उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने सदन में **NEET** परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है। मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें, निर्धारित करें।

संसदीय पैनल ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे तीनों आरोप सही पाए

संसदीय जांच पैनल ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए आरोप सही पाए हैं। यह मामला उनके सरकारी आवास के स्टोररूम से नकदी मिलने से जुड़ा है। पैनल की रिपोर्ट बुधवार, 12 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोररूम में 500 रुपए के नोटों की काफी मात्रा मिली थी, लेकिन जस्टिस वर्मा नकदी के स्रोत, मालिकाना हक या वहां मौजूद होने की संतोषजनक वजह नहीं बता सके। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

कोलंबिया भूकंप के 2 दिन बाद मलबे में मिला नवजात

5 मंजिला इमारत गिरी थी, रेस्क्यू टीम को आवाज देकर बोला शख्स- यहां बच्चे के साथ हूं

नई दिल्ली। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार रात आए 7.4 तीव्रता के भूकंप के करीब 48 घंटे बाद मलबे से एक बच्चे को जिंदा निकाला गया। बच्चा एक गिरी हुई पांच मंजिला रिहायशी इमारत के मलबे में फंसा था। उसके साथ एक आदमी भी दबा हुआ था। यह रेस्क्यू बुधवार को भूकंप के बाद चल रहे तीसरे दिन के सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, रेस्क्यू टीम ने बताया कि उन्हें मलबे के नीचे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। आदमी ने कहा- 'हां, मैं यहीं हूं। मैं एक बच्चे के साथ हूं।' इसके बाद मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम और बाकी लोगों ने तुरंत हाथों से मलबा हटाना शुरू कर दिया। एक भारी कंक्रीट स्लैब के नीचे एक शख्स और नवजात बच्चा फंसा हुआ था। लोगों ने स्लैब को उठाया और दोनों को बचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बच्चे का सिर बैंगनी जैसा पड़ गया था, क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी।

भारत बोला- हम हर संभव मदद के लिए तैयार

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कोलंबिया में जान-माल के नुकसान से वे बेहद दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर कोलंबिया को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।

बेघर लोगों को आर्थिक मदद देगा कोलंबिया

कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रिसाराल्दा प्रांत में प्रभावित लोगों को 3 महीने तक घरेलू सेवाओं के बिल से राहत देने का आदेश दिया है। जिन लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, उन्हें अस्थायी आवास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बाद में घरों की मरम्मत और दोबारा निर्माण में भी सहायता दी जाएगी।

परेरा में सबसे ज्यादा मौतें

परेरा शहर में अकेले 60 लोगों की मौत हुई है। करीब 5 लाख की आबादी वाला यह शहर भूकंप के केंद्र से 64 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। राजधानी बोगोटा समेत कई शहरों में भी तेज झटके महसूस किए गए। एहतियात के तौर पर लोग इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए।

चोको और रिसाराल्डा में भारी नुकसान

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप सोमवार सुबह करीब 7:34 बजे आया। इसका केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पालमार के पास था। भूकंप की गहराई 107 किलोमीटर थी।

कोलंबिया में ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं

कोलंबिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यहां हर साल हजार से ज्यादा छोटे-बड़े भूकंप आते हैं। कोलंबिया में बार-बार भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह देश रिंग ऑफ फायर नाम के भूकंप और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में आता है। यहां नाजका, कोकोस और दक्षिण अमेरिकी जैसी कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इनमें से एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती रहती है। इसी वजह से जमीन के अंदर लगातार हलचल होती रहती है, जिससे अक्सर तेज भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं।

दीपके बोले- जंतर-मंतर सीजन 2 जल्द आएगा

हमें दिल्ली में बैठक के लिए हॉल नहीं मिला, BJP पर धमकी देने का आरोप लगाया

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बुधवार को छात्र आंदोलन की तर्ज पर एक और प्रदर्शन जल्द शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने इसे 'जंतर-मंतर सीजन 2' बताया। दीपके ने आरोप लगाया, हमने आज दिल्ली में अपने वॉलेंटियर्स की बैठक रखी थी। हम एक हॉल की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। सभी लोग कहते रहे कि ऊपर से दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया,' इन सब के पीछे BJP का हाथ है। इस तरह की कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे।' नीट पेपर लीक के मामले में सीजेपी ने जंतर-मंतर पर 37 दिन धरना प्रदर्शन किया था।

सीजेपी प्रवक्ता बोले- देशभर में हो रहे प्रदर्शन

चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी अब देशभर में 'लिसनिंग टूर' शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों की बात सुनी जा सके। उन्होंने बताया कि पार्टी एक कैंपेन चलाएगी और स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को दिल्ली के एक पब्लिक गार्डन में मीटिंग की। आरोप लगाया कि भाजपा की वजह से किसी ने बैठक के लिए हॉल नहीं दिया।

सीजेआई सूर्यकांत के बयान के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा। उन्होंने कहा- कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या **RTI** एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। 16 मई को रात 12 बजे अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का सोशल मीडिया अकाउंट बनाए। एक वेबसाइट भी बनाई गई। एक्स पर एक गूगल फॉर्म जारी हुआ। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी लिखी एक तस्वीर के साथ कैप्शन था- सभी कॉकरोचों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो लिंक पर क्लिक करें। 17 से 20 मई तक कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स लगातार बढ़े, लेकिन 21 मई को इसके अकाउंट बंद कर दिए गए। इसी दिन कॉकरोच इज बैक नाम से दूसरा अकाउंट बन गया। 22 मई को सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। 24 मई को वेबसाइट पर ऑनलाइन पिटीशन जारी की गई। इस पर प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था।

बेंगलुरु जेल में प्रज्वल रेवन्ना के पास फोन मिला

पेन ड्राइव भी बरामद; पूर्व पीएम का पोता रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा

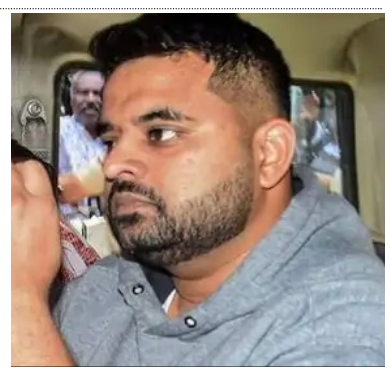

बेंगलुरु। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल और पेन ड्राइव मिली है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने मंगलवार को जेल में छापेमारी की थी। जेल DGP अलोक कुमार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। प्रज्वल जनता दल (सेक्युलर) के विधायक एचडी रेवन्ना का बेटा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है। वह महिलाओं से रेप केस में अगस्त 2025 से उम्रकैद की सजा काट रहा है। उन्होंने बताया कि घटना सामने आने के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड किया गया है। SP को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। प्रज्वल के परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला ने अप्रैल 2024 में उसके खिलाफ स्न्नद्धक्रदर्ज कराई थी। उसने प्रज्वल पर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। प्रज्वल के खिलाफ रेप, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। प्रज्वल को एक अगस्त 2025 को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। उसे अगले दिन 2 अगस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और 11.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें से 11.25 लाख रुपए पीड़ति को देने का निर्देश दिया गया था। प्रज्वल के खिलाफ रेप के तीन और मामले चल रहे हैं। इन मामलों की सुनवाई अभी बाकी है।

मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड, 7 की मौत

पहाड़ का हिस्सा तीन घरों पर गिरा, मलबे में दबे लोगों को कैमरों से तलाशा

मुंबई। मुंबई के घाटकोपर के चिराग नगर में बुधवार सुबह 3:48 बजे लैंडस्लाइड से पहाड़ी का मलबा 3 घरों पर गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत और 7 घायल हुए हैं, जबकि 3-4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम विक्टिम-डिटेक्शन कैमरों से तलाश कर रही है। गली बेहद संकरी है, भारी मशीनें मौके तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मलबा पहले ब्रेकर से तोड़ा जा रहा है, फिर बाल्टियों से हाथ से हटाया जा रहा है, जिससे रेस्क्यू में समय लग रहा है।

गलियों में एक बार में एक व्यक्ति का अंदर जाना संभव

अधिकारियों के मुताबिक, प्रभावित इलाके तक पहुंचने वाली गलियां इतनी संकरी हैं कि एक समय में मुश्किल से एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है और दो लोग आमने-सामने भी खड़े नहीं हो सकते। पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव अस्पताल भेज दिए गए हैं। वहीं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 18 साल के सोहेल अंसारी के सिर में चोट आई है, जबकि 14 साल के मोहम्मद अंसारी की पीठ में चोट लगी है।

मृतकों के परिवार को 4-4 लाख मुआवजा

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने घटनास्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं, हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति के इलाज के लिए 50 हजार देने की घोषणा की गई है। मेयर ने मौके पर मौजूद सभी एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। **BMC** के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ फायर ब्रिगेड, **NDRF**, पुलिस और अन्य टीमें लगातार मलबा हटाने और लोगों की तलाश में जुटी हैं। प्रशासन के मुताबिक, रेस्क्यू और इमरजेंसी ऑपरेशन अभी जारी है। **DCP** गणेश शिंदे ने बताया कि घाटकोपर पुलिस मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच कर रही है।

मुंबई में बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर आग लगी

ढाई साल के बच्चे समेत 2 की मौत; करीब 3 घंटे छत पर फंसे रहे 15 लोग

मुंबई। मुंबई के विले पार्ले इलाके में मंगलवार रात करीब 10 बजे रिहायशी इमारत शांता भवन की 11वीं मंजिल पर आग लग गई। हदसे में ढाई साल के बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में आठ लोग घायल हो गए। आग लगने के बाद करीब 15 लोग 3 घंटे तक बिल्डिंग की छत पर फंसे रहे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। नानावटी अस्पताल के मुताबिक ढाई साल के अबीर और 23 साल की अंकिता को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। आग बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, AC यूनिट, घरेलू सामान, सोफा, बेड, फॉल्स सीलिंग और किचन के बर्तनों में फैल गई, जो लगभग 4,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैल गई।

लेवल-1 से लेवल-2 तक पहुंची आग

मुंबई फायर ब्रिगेड ने रात 10:08 बजे आग को लेवल-1 यानी मामूली आग बताया। रात 10:16 बजे इसे लेवल-2 यानी मध्यम स्तर की आग कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस, इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी, एंबुलेंस सेवा और बीएमसी वार्ड का स्टाफ मौके पर पहुंचा। देर रात तक कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा।

रूस की तरफ से मध्यस्थ बनेंगे पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़

नई दिल्ली। रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को यूक्रेन के सरकारी बैंक ओश्चादबैंक से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद में अपना मध्यस्थ बनाया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला यूक्रेन और रूस के बीच 1998 में हुए द्विपक्षीय निवेश समझौते के तहत चल रहा है। ओश्चादबैंक का कहना है कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से उसे दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में अपनी संपत्तियां और कारोबार गंवाना पड़ा।

ट्रम्प ने माना- ईरान के डर से प्लेन बदलना पड़ा

हमला होता तो एयरफोर्स वन पर होता; ट्रक में छिपकर दूसरे विमान तक पहुंचे

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मान लिया है कि उन्होंने पिछले महीने तुर्किये में ईरान के डर से प्लेन बदला था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जिस प्लेन से NATO समिट में हिस्सा लेने गए थे उस पर हमले का सबसे ज्यादा खतरा था। ट्रम्प ने यह भी बताया कि उन्हें सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट के केटरिंग ट्रक में बैठाकर दूसरे विमान तक ले जाया गया।

ट्रम्प ने कहा- अगर कोई हमला होता तो उसी प्लेन को निशाना बनाया जाता। मैं वही करता हूं, जो सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं। मुझे लगातार धमकियां मिलती रहती हैं।

कतर के गिफ्ट किए प्लेन में बैठकर गए, मिलिट्री प्लेन से लौटे

इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि 8 जुलाई को अंकारा से रवाना होते समय ट्रम्प कैमरों के सामने बोइंग 747-8 एयर फोर्स वन में सवार हुए थे। यह विमान उन्हें कतर ने गिफ्ट किया था। इसके बाद एयरपोर्ट पर सामान और खाना पहुंचाने वाली केटरिंग गाड़ी की मदद से उन्हें चुपचाप अमेरिकी वायुसेना के वीआईपी सैन्य विमान सी-32ए तक ले जाया गया।

मीडिया को भी नहीं पता था कि ट्रम्प दूसरे विमान में हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी किसी दौरे पर जाते हैं, तो उनके साथ कुछ पत्रकार भी यात्रा करते हैं। सुरक्षा कारणों से हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन इन पत्रकारों को इतना जरूर पता होता है कि राष्ट्रपति किस विमान में हैं और कहां जा रहे हैं। तुर्किये से उड़ान भरते समय पत्रकारों को लगा कि ट्रम्प भी उसी पुराने एयर फोर्स वन में हैं, लेकिन हकीकत अलग थी। उड़ान के दौरान पत्रकारों को अपनी खिड़कियों के शेड नीचे रखने को कहा गया। यानी उन्हें बाहर देखने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सावधानी आमतौर पर तब बरती जाती है, जब विमान किसी खतरे वाले इलाके से गुजर रहा हो। बाद में पत्रकारों ने ट्रम्प से पूछा कि खिड़कियों के शेड बंद रखने को क्यों कहा गया था। ट्रम्प ने कहा, शायद हम एक खतरनाक फ्लाइट पर थे। उनकी सूची में सबसे ऊपर मेरा नाम है। अगर मैं मरूंगा, तो आप भी मरेंगे।

ट्रम्प वाला छोटा विमान पहले ब्रिटेन पहुंचा

ट्रम्प को लेकर छोटा सी-32ए विमान रात करीब 10:20 बजे ब्रिटेन के **RAF** मिल्डेनहॉल एयरबेस पहुंचा। इसके कुछ मिनट बाद पुराना एयरफोर्स वन भी वहां पहुंच गया। इस विमान में पत्रकार सवार थे। इसके बाद उन्हें चुपचाप पुराने एयर फोर्स वन में लाया गया। कुछ देर बाद वे उसी विमान से उतरते दिखे, जिससे पत्रकारों को लगा कि वे पूरी यात्रा उसी में कर रहे थे। हालांकि, यह साफ नहीं है कि छ्र-32 से उतरने के बाद ट्रम्प पुराने एयरफोर्स वन तक कैसे पहुंचे। ट्रम्प ने पत्रकारों की तरफ हाथ हिलाया, लेकिन उनसे बात नहीं की। इसके बाद फिर वे आधिकारिक प्लेन यानी कि एयरफोर्स वन में बैठ गए और उसी से अमेरिका पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले की सुनवाई टली

इंदौर हाईकोर्ट के मंदिर घोषित करने के फैसले को चुनौती; मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं लगीं

धार। मध्यप्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले 5 अगस्त को भी सुनवाई टल गई थी और कोर्ट ने अगली तारीख 12 अगस्त तय की थी। कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने से मामले में अगली सुनवाई का इंतजार है। दरअसल, 15 मई 2026 को इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू समाज को वहां रोजाना पूजा करने की अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट में पांच याचिकाएं दायर की थीं।

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अंतरिम आदेश

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि मुस्लिम समाज के लिए हर शुक्रवार जुमे की नमाज अदा करने के लिए भोजशाला के पास ही किसी खाली वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए। इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रशासन ने चालीस पीर दरगाह के पास स्थित खाली जमीन पर नमाज की व्यवस्था करने की बात कही। इस जगह को समतल भी कराया गया था। मुस्लिम समाज ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई। समाज के लोगों का कहना था कि चालीस पीर दरगाह भोजशाला से काफी दूर है।

पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट: ISI से जुड़ा, फर्जी दस्तावेजों पर भारत में रह रहा था; कोलकाता के कारपेंटर ने की थी मदद

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल STF ने बुधवार को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर से संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से संबंध हैं। वह जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। STF सूत्रों के अनुसार आतंकी की पहचान राना रऊफ के रूप में हुई है। भारत में वहाब आलम के नाम से रह रहा था। बांग्लादेश भागने की कोशिश में था। उसे 24 परगना जिले के बनगांव से गिरफ्तार किया गया।

2012 में नेपाल के रास्ते भारत आया था

एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, रऊफ मूल रूप से पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। वह 2012 में नेपाल के रास्ते भारत आया था। इसके बाद से पश्चिम बंगाल में रहने लगा। शुरुआती जांच में उसके वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान भेजने की बात सामने आई है। **STF** ने मंगलवार रात टोपसिया से एक व्यक्ति को गिरफ्तार है, उसका रऊफ से सीधा संपर्क था और उसने कई तरह से उसकी मदद की थी; हालांकि, उन्होंने उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया।

कोलकाता के कारपेंटर ने बनवाए फर्जी दस्तावेज

रऊफ ने बताया कि कोलकाता के टॉपसिया इलाके में रहने वाले एक कारपेंटर ने उसके लिए फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए। इनमें वोटर कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। रऊफ और कारपेंटर नेपाल में मिले थे।

नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ क्यों आसान है

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा (ओपन बॉर्डर) की व्यवस्था ब्रिटिश शासन की विरासत है, जिसे 1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना था। संधि के प्रावधानों के तहत, दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे के क्षेत्र में बिना वीजा या पासपोर्ट के आने-जाने, रहने, संपत्ति खरीदने और काम करने की स्वतंत्रता दी गई है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रदीप कुमार सोलंकी द्वारा महानगर मल्टीमीडिया प्रा. लि. जी-848, फेज 3, रीको सीतापुरा, जयपुर (राज.) से मुद्रित एवं 227-हीरालाल की गली, झालाना, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित।
सम्पादकः प्रदीप कुमार सोलंकी, मो. 93510-01100, Email: atulyasansar@gmail.com संपादकीय कार्यालयः जगतपुरा फ्लाईओवर के पास, जगतपुरा जयपुर।